है, उस एरिया में उसका कंटेंट ज्यादा है, इसलिए वहां पर पानी में भी उसका कंटेंट ज्यादा है। उसके कंटेंट के ज्यादा होने के कारण वहां के पानी से लोग सफर करते हैं। इसका तरीका यही है कि इनको बाहर से पानी दिया जाए या इस कंटेमिनेशन को समाप्त करके इस पानी का उपयोग किया जाए। अब यह किसी-किसी जगह पर है, किसी-किसी जगह पर नहीं है। कुछ एरियाज़ हैं, जैसे गैंगेटिक प्लेन्स है, इसके साइड में आर्सेनिक काफी है। उसी तरीके से तेलंगाना रीजन में फ्लोराइड का कंटेंट काफी है। कुछ वेस्ट बंगाल के एरिया में है। आपने कुछ स्टेट्स के नाम लिए हैं। इसका कारण प्राकृतिक है, यह कोई मैन मेड नहीं है, लेकिन इसको एड्रेस करने की आवश्यकता है और हम इसको एड्रेस कर रहे हैं।

SHRIMATI AMBIKA SONI: Sir, I am sure, while he has been the Health Minister, he must have to come to know that in Punjab particularly, because it has been the granary for the whole country, due to overuse of fertilizers and pesticides, the quality of water has greatly deteriorated. This has caused severe problem of cancer and many people are becoming physically and mentally-challenged due to this. The Minister, in his answer, has said that he is giving special help monetarily also to those States which are affected. I would like to ask the hon. Minister, considering the fact that how Punjab looks after the country in the matter of granary, whether any special amount has been given to Punjab? What is the amount which has been given? Has that amount been spent? And, what is the outcome of that expenditure?

SHRI JAGAT PRAKASH NADDA: Sir, first of all, I share the concern of the hon. Member. It is a fact that in few areas of Punjab, because of use of fertilizers and other things, arsenic content is quite large and cancer patients are much more. As far as the funds are concerned, every State is being given funds. I will give the details of it. At this point of time, I do not have the details. But, certainly, this issue has to be addressed and the Government of India is very enlightened about the issue. We would like to give the required amount of funds, which is needed for that purpose. But, certainly, we are upgrading the Institute of Cancer in Punjab and other facilities are also being given. Recently, our hon. Finance Minister has said that we are going to open one AIIMS in Punjab. So, all this is going to take care, as far as the health facilities are concerned. But Punjab has been given ₹ 87 crore in this financial year.

SHRIMATI AMBIKA SONI: Has there been any monitoring?

MR. CHAIRMAN: Now, Question No. 202.

अप्रचालित आयुध कारखाने

*202. **श्री हरिवंश**: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में ऐसे भी आयुध कारखाने हैं, जो हर तरह से बनकर तैयार हैं, किंतु उनमें अभी तक काम शुरू नहीं हो पाया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे आयुध कारखानों की संख्या कितनी है और इन कारखानों पर अब तक कितनी धनराशि व्यय की गई है; और

(ग) नालंदा स्थित आयुध कारखाने से संबंधित स्थिति का ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्री (श्री मनोहर पर्रिकर): (क) से (ग)एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) और (ख) जी, नहीं। तथापि, आयुध निर्माणी बोर्ड अर्थात बिहार स्थित आयुध निर्माणी, नालंदा और उत्तर प्रदेश स्थित आयुध निर्माणी, कोरवा में दो ग्रीन फील्ड परियोजनाएं हैं, जो क्रमशः बाई मॉड्यूलर चार्ज सिस्टम तथा क्लोज क्वार्टर बैटल कारबाइन के स्वदेशी विनिर्माण के लिए स्थापित की जा रही हैं। अब तक आयुध निर्माणी नालंदा तथा आयुध निर्माणी परियोजना, कोरवा में क्रमशः 934 करोड़ रुपए तथा 282 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है।

(ग) आयुध निर्माणी, नालंदा की स्थिति इस प्रकार हैः

(i) नाइट्रोग्लिसरीन (एनजी) संयंत्र, नाइट्रोसेल्युलोज (एनसी) संयंत्र तथा सल्फ्यूरिक एसिड कन्संट्रेशन/नाइट्रिक एसिड कन्संट्रेशन संयंत्र स्थापित किए गए हैं।

(ii) बाई मॉड्यूलर चार्ज सिस्टम (बीएमसीएस) संयंत्र : दक्षिण अफ्रीका के मै0 डेनेल (पीटीवाई.), जिनके साथ वर्ष 2002 में प्रौद्योगिकी हस्तांतरण हेतु एक करार किया गया था, को कथित गड़बड़ियों के कारण रक्षा मंत्रालय द्वारा वर्ष 2005 में विवर्जित कर दिया गया था। इसके बाद आयुध निर्माणी बोर्ड ने मै0 आईएमआई, इजराइल के साथ मार्च, 2009 में मुख्य बीएमसीएस संयंत्र की आपूर्ति के लिए एक संविदा की थी। तथापि, मार्च, 2012 में, सीबीआई की सिफारिशों के आधार पर मै0 आईएमआई, इजराइल को 10 वर्ष की अवधि के लिए विवर्जित किए जाने पर आयुध निर्माणी बोर्ड ने इस संविदा को रद्द कर दिया था। मुख्य बीएमसीएस संयंत्र के लिए मै0 आईएमआई, इजराइल के साथ संविदा रद्द किए जाने के बाद, आयुध निर्माणी बोर्ड ने स्वदेशी स्रोतों के जरिए बीएमसीएस के विनिर्माण के लिए पांच अलग-अलग संयंत्रों (एनसी-एनजी पेस्ट, सिंगल बेस प्रोपेलेंट, ट्रिपल बेस प्रोपेलेंट, कंबस्टिबल कारट्रिज केस तथा चार्ज असेंबली) के वास्ते अधिप्राप्ति कार्रवाई आरंभ की। आयुद्ध निर्माणी बोर्ड को पांच अलग-अलग संयंत्रों के लिए तकनीकी तथा वाणिज्यिक ऑफर प्राप्त हुए हैं और उनका आयुध निर्माणी बोर्ड में तकनीकी मूल्यांकन किया जा रहा है।

Non-functioning ordnance factories

†*202. SHRI HARIVANSH: Will the Minister of DEFENCE be pleased to state:

(a) whether there are such ordnance factories in the country which are complete in all respects but yet to start functioning;

† Original notice of the question was received in Hindi.

(b) if so, the number of such ordnance factories and the expenditure incurred on these factories, so far; and

(c) the details of status of the Nalanda Ordnance Factory?

THE MINISTER OF DEFENCE (SHRI MANOHAR PARRIKAR): (a) to (c) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) and (b) No, Sir. However, there are two green field projects in Ordnance Factory Board (OFB) i.e. Ordnance Factory, Nalanda in Bihar and Ordnance Factory, Korwa in UP; which are being set up for indigenous manufacturing of Bi-modular Charge System and Close Quarter Battle Carbine respectively. The investment made in Ordnance Factory, Nalanda and Ordnance Factory Project, Korwa so far, has been ₹ 934 Crore and ₹ 282 crore respectively.

(c) The status of Ordnance Factory, Nalanda is as under:

(i) Nitroglycerine (NG) Plant, Nitrocellulose (NC) Plant and Sulphuric Acid Concentration/Nitric Acid Concentration Plant have been erected.

(ii) Bi-modular Charge System (BMCS) Plant: M/s Denel (PTY) of South Africa with whom there was an agreement for transfer of technology in the year 2002, was debarred by the Ministry of defence, in 2005, on account of alleged malpractices. Subsequently, OFB had entered into a contract with M/s IMI, Israel, in March 2009, for supply of main BMCS plant. However, the contract was cancelled by OFB, in March 2012, when M/s IMI Israel got debarred for a period of ten years based on the recommendations of CBI. Consequent to the cancellation of contract with M/s IMI, Israel for the main BMCS plant, Ordnance Factory Board (OFB) had initiated procurement action for five individual plants (NC-NG Paste, Single Base Propellant, Triple Base Propellant, Combustible Cartridge Case and Charge Assembly) through indigenous sources for manufacture of BMCS. OFB has received technical and commercial offers for the five individual plants and they are under Technical Evaluation at Ordnance Factory Board.

श्री हरिवंश : माननीय सभापति जी, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं, लिखित उत्तर में उन्होंने यह सूचना भी दी है कि बिहार स्थित नालन्दा और उत्तर प्रदेश स्थित

कोरवा ordinance factories पर अब तक लगभग क्रमश: 934 करोड़ रुपये और 282 करोड़ रुपये निवेश हो चुके हैं, लेकिन अब तक उनमें प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। उनकी यह सूचना भी सही है कि नालन्दा में BMCS system technology transfer की वजह से यह विलम्ब हुआ है। दक्षिण अफ्रीका और इज़राइल की जिन दो कम्पनियों से करार हुआ, जांच के क्रम में उन पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया, इसीलिए यह विलम्ब हुआ।

मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि इतना खर्च होने के बाद भी प्रोडक्शन होने की स्थिति कब तक बनेगी? उल्लेखनीय है कि नालन्दा आयुध फैक्ट्री की योजना 10वीं पंचवर्षीय योजना में बनी, जो 12वीं योजना में पहुंच गई है। सरकार के पास स्पष्ट योजना क्या है? कब तक इन दोनों फैक्ट्रीज़ में प्रोडक्शन शुरू होगा?

SHRI MANOHAR PARRIKAR: This is a story of two VIP areas where ₹ 1,216 crores have been spent without any output so far. As far as Nalanda is concerned, we have spent ₹ 934 crore. 2001 में उसके लिए 941.31 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था और South Africa की जो M/s Denel Co. है, उनके साथ उसका technical collaboration हुआ था।

In fact, that company was blacklisted and without going into the real details, the Government, at that time, in 2006 or 2007, debarred the Government department from having any further relations with the company. I am surprised because we have actually paid the full transfer fee to the company. ₹ 66.14 crore were paid to the company, लेकिन उसके बाद में debarment हो गया, तो हम लोग उनसे जो लेना चाहते थे, वह नहीं ले सके, लेकिन उनको पैसा पूरा दिया जा चुका है। Subsequently, M/s IMI, Israel के साथ भी contract किया था, वह भी CBI के घेरे में आ गयी। Ultimately, today the position is that after spending ₹ 931.81 plus whatever is the interest, we do not have full set up. अभी new set up बनाने की कोशिश चल रही है। In the meantime, production has been initiated by getting material from other plants. Like, from Chandrapur, we are getting NG (Nitroglycerine) and NC (Nitrocellulose), उनकी पेस्ट और बाकी चीज़ें, and, 2,000 of them have been tested. ₹ 50,000-order has also been placed. Meantime, production शुरू करने की कोशिश चालू है। This is the story of Nalanda.

The story of Korwa is still wonderful. Korwa is in Amethi. Obviously, you know the reasons. We have not finalized with whom we are going to have the carbine contract. It is still in the trial and testing stage. But we have already spent ₹ 282 crore by virtually snatching away 30 acres of land from HAL and constructing factory there, and, spending ₹ 141 crores on state-of-the-art machinery and the factory is not performing. हमारी कोशिश है कि दोनों जगह पर प्रोडक्शन किया जाए। The only problem which I found is that the capacity of Korwa is 45,000 carbines. Sir, our total requirement of close combat and protective carbine is around 3.6 lakhs. So, at full speed, we do not even have the order position of seven, eight years, even if we manage to start the

unit. Besides that we have a rifle factory, which has excess production capacity. I am working on the exact situation.

MR. CHAIRMAN: Second question.

श्री हरिवंश : धन्यवाद, सभापति जी। इससे पहले कि मैं दूसरा सप्लिमेंट्री पूछूं, मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा, चूंकि माननीय मंत्री जी देश में बहुत सक्षम मंत्रियों के रूप में माने जाते हैं, लेकिन उन्होंने टिप्पणी की है कि ये दोनों वीआईपी इलाके की आर्डिनेंस फैक्ट्रीज़ हैं। मैं मानता हूं कि देश में अगर कहीं पर भी कोई फैक्ट्री है, तो वह इस देश की फैक्ट्री है, किसी वीआईपी इलाके की फैक्ट्री नहीं है। वे जिस भी हालत में हों, उनको बेहतर करना और उनको चलाना सरकार का मकसद होना चाहिए।

महोदय, मेरा दूसरा सवाल है, अगर सभी Ordnance Factories फंक्शनल हैं, तो इस देश में डिफेंस के अनेक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स विलम्ब से क्यों चल रहे हैं? अगर मैं नाम गिनवाऊँ तो series of names मेरे पास हैं। T-72 Tank है, T-90 Tank है, जिन्हें पूरा होने में चार-चार, पाँच-पाँच वर्ष लग जाते हैं, तब भी 50% काम पूरा नहीं होता है।

MR. CHAIRMAN: Quickly please.

श्री हरिवंश : सर, मैं जानना चाहता हूं कि ये जो Ordnance Factories हैं, ये काम पूरा कर पाने में सक्षम नहीं हैं या Ordnance Factories की संख्या कम है अथवा हमारे यहां एक्सपर्ट्स कम हैं अथवा फिर हमारा R&D कमजोर है?

MR. CHAIRMAN: Question please.

श्री हरिवंश : सर, ये सभी सवाल एक ही प्रश्न से जुड़े हुए हैं।

WRITTEN ANSWERS TO STARRED QUESTIONS

Precautionary measures to combat Dengue disease

*203. SHRIMATI SAROJINI HEMBRAM: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) whether Government has taken effective precautionary measures to combat the dengue disease in the country keeping in view the approaching dengue season, if so, the details thereof; and

(b) if not, the reasons therefor and the number of dengue cases reported in the country, State-wise, during the last three months?

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI JAGAT PRAKASH NADDA): (a) Government of India has taken the following precautionary measures to combat the dengue disease in the country:

1. NVBDCP is closely monitoring the situation through the reports received from the State Health authorities.